>

Title: Need to provide civic amenities in slum areas in Mumbai, Maharashtra -laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश में विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई में केन्द्र सरकार और उसके अधीन केन्द्रीय विभागों के स्वामित्व वाली नमक क्षेत्र भूमि या रेलवे, पोत न्यास और रक्षा के स्वामित्व वाली जमीन के साथ-साथ राज्य सरकार के वन विभाग एवं अन्य विभागों के स्वामित्व वाली भूमि पर विगत कई वर्षों से भी अधिक समय से गरीब लोग बसे हुए है ।

इन बस्तियों में शौचालय, सीवर पाइप लाइन, पेयजल, विद्युत इत्यादि जरूरी नागरिक मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों की मरम्मत कराने में भी इनको अनेकों प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इनमें रहने वाले लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब लोगों को आवास सुलभ कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

अतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब लोगों को आवास सुलभ कराये जाने की महत्वाकांक्षी योजना एवं देश की 75वीं स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों विशेषतः महाराष्ट्र सरकार को सरकारी भूमि पर स्थापित सभी बस्तियों में शौचालय, सीवर पाईप लाइन, पेयजल, विद्युत, मकान मरम्मत इत्यादि की सुविधायें वर्ष 2022 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

ऐसा करने से न केवल गरीबों को स्थायी आवास और जरूरी मूलभूत नागरिक सुविधायें मिल सकेंगी बल्कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश

और विदेश की धरती से गरीबों के प्रति व्यक्त किये गये बयान और भावना तथा उनकी वर्ष 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध कराये जाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी साकार करने में पूर्णतः सफलता मिलेगी ।